GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 6
November-December: 2025

नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव : भारत के लिए चुनौति

डॉ0 जितेन्द्र कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग
दी0 द0 उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
मो0 न0 – 8182834300

सारांश

चीन भारत के हिमालयी पड़ोसी नेपाल की ओर अपना हाथ बढ़ा रहा है, जो अपने उत्तरी मोर्चे पर उभर रही संभावनाओं की ओर काफी आकर्षित है। नेपाल में चीन के बढ़ते पदचिह्न भारत को कैसे प्रभावित करते हैं? नेपाल में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में भारत की सफलता की संभावनाओं की जांच करता है, और दो व्यापक कारक प्रस्तुत करता हैरू चीन को चुनौती देने के लिए नई दिल्ली की समग्र क्षमता, और नेपाल के प्रति अपने स्वयं के विवादास्पद दृष्टिकोणों को संबोधित करने के लिए भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति। यह तर्क देता है कि बदलते भू–राजनीतिक संदर्भ में, एक मजबूत संप्रभु नेपाल जो एक स्वतंत्र विदेश नीति का प्रयोग कर सकता है। नेपाल में चीन के प्रवेश के संबंध में, भारत के लिए एक विकल्प यह होगा कि वह चीनी निवेश द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास जैसी परियोजनाओं के माध्यम से, पड़ोसियों के साथ अपने सहयोग में विविधता लाने के लिए नेपाल के विकल्पों को अवरुद्ध करने का प्रयास करके यथास्थिति की रक्षा करे। हालाँकि, ऐसी नीति विफल होना तय है क्योंकि नेपाल चीन सहित विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग के अवसरों का लाभ उठाने के लिए दृढ़ है। बाहरी हस्तक्षेप के मुद्दे को संबोधित करते हुए, नेपाली विदेश मंत्री पी. ग्यावली ने हाल ही में कहा, ष्हम एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचना चाहते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत, चीन और अन्य के साथ द्विपक्षीय चर्चा में आंतरिक मामले कभी भी मुद्दे नहीं होंगे।

मुख्य शब्द :– भारत–नेपाल सम्बन्ध, स्त्रातजिक महत्व**,** राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन, विदेश नीति ।

प्रस्तावना – 29 मिलियन लोगों की आबादी के साथ नेपाल दुनिया का 45वां सबसे बड़ा देश है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग बांग्लादेश के बराबर है और श्रीलंका का दोगुना है। इस प्रकार, यदि केवल अपने आकार के लिए, नेपाल एक राष्ट्र–राज्य के लिए एक जागीरदार होने के लिए बहुत बड़ा है। देश को अपने इतिहास पर गर्व है कि वह कभी उपनिवेश नहीं रहा और उसकी एक महत्वपूर्ण भू–रणनीतिक स्थिति है, जिसके दोनों ओर भारत और चीन हैं। हालांकि, सौहार्दपूर्ण राजनयिक संबंधों की पारंपरिक धारणाओं के विपरीत, नेपाल और भारत के एक–दूसरे को देखने के तरीके में काफी अंतर है। स्वतंत्रता

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 6
November-December: 2025

के बाद, भारत ने ब्रिटेन के दृष्टिकोण का अनुकरण किया नेपाल के साथ एक संधि–आधारित संबंध होने के कारण, जिसके कारण नेपाल ने भारत के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। नेपाल के शासक अभिजात वर्ग–विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान देश के विशेषाधिकार प्राप्त भू–रणनीतिक साख के संदर्भ में पश्चिम द्वारा प्रोत्साहित किए गए राजशाही का विचार था कि भारत ने नेपाल के साथ विशेष संबंध की भावना के अनुसार व्यवहार नहीं किया। नेपाल की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए भारत कई दशकों तक हिमालयी राष्ट्र को अपने पाले में रखने में कामयाब रहा। भारतीय प्रतिष्ठान ने इसे अपनी नीतियों की सफलता के रूप में देखा जिसने अपने छोटे भाई के साथ एक स्थिर संबंध उत्पन्न किया। हालाँकि, शीत युद्ध के बाद के युग में, यह भारत नहीं था, बल्कि पश्चिमी संस्थानों और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने नेपाल के शासन को ध्यान से देखने का बीड़ा उठाया था। अब, चीन के नए गणराज्य में प्रवेश करने के साथ, निश्चय ही, नेपाल में चीन की व्यस्तता कोई नई बात नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात– और नेपाल में इसे जिस तरह से चित्रित किया जाता है, उसके विपरीत–यह पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है। हालाँकि, जुड़ाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन की नई आर्थिक शक्ति अभी तक बेजोड़ है। चीन के साथ जुड़ने की नेपाल की उत्सुकता पर्यवेक्षकों के लिए रूचिकर रही है और इसे प्रधान मंत्री खडगा प्रसाद शर्मा ओली की भारत से और अधिक हासिल करने की रणनीति के रूप में गलत तरीके से व्याख्या किया गया है। हालाँकि, वर्तमान दृष्टिकोण नेपाल की एक विविध विदेश नीति और भागीदारों को आगे बढ़ाने की लंबी परंपरा में पूरी तरह से फिट बैठता है, इसकी प्रमुख भू–रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाता है। ओली की सरकार का उद्देश्य चीन के साथ नेपाल के संबंधों को भारत के साथ साझा किए गए संबंधों से स्वतंत्र रखना है। सवाल यह है कि चीन की बढ़ती नजदीकियों से भारत की बेचौनी को देखते हुए क्या नेपाल इसे हासिल कर पाएगा। नेपाल और चीन दोनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे एक दूसरे के साथ गंभीर संबंध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ओली की हाल की चीन यात्रा के दौरान, बीजिंग में दक्षिण एशिया के विशेषज्ञ हू शिशेंग ने कहा, ष्हमारी ख्चीन की, नीति स्पष्ट है – यदि आप ख्भारत, हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, यदि नहीं, तो कम से कम हमारे काम में बाधा न डालें। इस रुख के आलोक में, नेपाल की नीतिगत प्रेरणा को समझना महत्वपूर्ण है। काठमांडू में लंबे समय से नई दिल्ली को संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए कठिन और स्वार्थी के रूप में माना जाता था, जिसने बदले में भारत की एक अप्रिय छवि पेश की। इसके सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में विभिन्न नदी संधियाँ, नियमित सीमा–अतिक्रमण की शिकायतों का जवाब देने में अनिच्छा, सीमा पर उच्च–संरचना का निर्माण, बाढ़ की शिकायतें, सशस्त्र सीमा बलों का कठोर व्यवहार, व्यापार और पारगमन संकट और प्रतिबंध शामिल हैं। ,इन अनुभवों ने नेपाल को अन्य विकल्पों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। चीन

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 6
November-December: 2025

के लिए नेपाल की जरूरत चीन–नेपाल संबंधों में किसी भी संभावित चुनौतियों से कहीं अधिक है, और ओली के लिए नेपाली ष्नागरिकों का जनादेशष उसी मजबूत इच्छा को दर्शाता है। इस प्रकार, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों ने भारत के खिलाफ लगातार विरोध किया है, और नेपाली कांग्रेस ने भी भारत के इस दृष्टिकोण पर व्यापक राजनीतिक सहमति का संकेत देते हुए, आरक्षण दिखाया है। ऐसे ऐतिहासिक कारण हैं जो नेपाल–भारत द्विपक्षीय संबंधों की गतिशीलता की व्याख्या करते हैं। प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने के लिए, भारत को कार्य करने के लिए आत्मविश्वास के साथ–साथ पर्याप्त सॉफ्ट पावर के साथ–साथ हार्ड पावर की भी आवश्यकता है। जैसा कि विद्वान अपर्णा पांडे का तर्क है, प्रभाव के क्षेत्र का प्रबंधन न केवल दूसरों को यह बताने का कार्य है कि क्या करना है बल्कि उन संसाधनों को खर्च करने में सक्षम होना है जो प्रतियोगियों को जगह नहीं देते हैं। राजा महेंद्र के युग के पूर्व प्रधान मंत्री कीर्ति निधि बिष्ट ने एक बार कहा था, भारत ने उन्हें (पीएम बिस्ता) अपना आपा खो दिया क्योंकि उस समय जब भारत आर्थिक रूप से महत्वहीन था, तब भी नेपाल पर उसकी अनुचित मांग थी। आर्थिक सीमाओं का एक संयोजन, भारत की राजनीतिक हेरफेर, चीनी घुसपैठ, और नेपाल के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों की पहुंच ने धीरे–धीरे संबंधों में विविधता लाने की इच्छा को बढ़ा दिया। इस तरह की महत्वाकांक्षाएं नेपाल में लगातार सरकारों का केंद्रीय तत्व रही हैं, जिससे भारत के साथ टकराव बढ़ गया है।

भारत–नेपाल संबंधों की प्रकृति हमेशा से मिली–जुली रही है। इसके प्रावधानों और प्रोटोकॉल के कारण, 1950 की संधि जल्दी ही विवादास्पद हो गई और द्विपक्षीय संबंधों के संघर्षपूर्ण स्वर को स्थापित किया। 1950 की भारत–नेपाल शांति और मैत्री संधि (1950 संधि अनुच्छेद 5, विनिमय पत्र अनुच्छेद 2, भारत–नेपाल सुरक्षा सहयोग समझौता, 1965 अनुच्छेद 5) के प्रावधान, नेपाल को एक सहयोगी और भारत की सुरक्षा के तहत एक राज्य के रूप में विवश करते हैं। 1988 में, चीन से विमान भेदी बंदूकें खरीदने के राजा बीरेंद्र के फैसले ने तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव केपीएस मेनन को नेपाल को उसके अस्तित्व की अनिश्चितता के बारे में चेतावनी देने के लिए प्रेरित किया। इन वर्षों में, दोनों देशों के बीच असंगति केवल विभिन्न क्षेत्रों में खराब हुई है।

विवाद के क्षेत्र सीमा, जल, वाणिज्य – दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हाल के उदाहरणों से पता चलता है कि कुछ मामलों में श्रम के मुक्त सीमा पार आंदोलन के प्रभाव ऐसे होते हैं जो एकीकरण की संस्था के विपरीत होते हैं, और यहां तक कि नुकसान भी पहुंचाते हैं। यह बदले में लोकलुभावनवाद और उग्रवाद को जन्म देता है। नेपाल ऐसे ही एक मामले का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों देशों के विषम आकार और संधि–आधारित असमान व्यवहार के कारण भारत के प्रति नेपाल के आरक्षण को देखते हुए, खुली सीमा हमेशा से ही विवाद का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, सिवाय उन समुदायों और व्यापारिक समूहों के जो

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 6
November-December: 2025

इससे सीधे लाभान्वित होते हैं। सीमा पार मुक्त आवाजाही की प्रथा आपसी भेदभाव का विषय बन गई है। संधि (अनुच्छेद 6 और 7) में प्रदान किए गए अनुसार कोई भी पक्ष राष्ट्रीय उपचार या पारस्परिक उपचार प्रदान नहीं करता है। इसने केवल कई शिकायतें की हैं, और सीमा पर समुदायों के साथ–साथ व्यवसायों को भी नकारात्मक दुष्प्रभावों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। एक्सचेंज के पत्र के अनुच्छेद 3 से पता चलता है कि भारत नेपाल में भारतीयों के साथ मुक्त प्रतिस्पर्धा से नेपालियों के लिए अस्थायी सुरक्षा के लिए सहमत है। हालांकि, चूंकि दोनों पक्ष ठोस शर्तों पर कभी सहमत नहीं हुए, इसलिए कार्यान्वयन रुक गया था। भारत इस मामले की संवेदनशील प्रकृति और इसके चुनावी निहितार्थों के साथ–साथ नेपाल के एक नई दिशा में संभावित प्रस्थान को देखते हुए, संधि को संशोधित करने की नेपाल की मांग से निपटने के लिए अनिच्छुक रहा है। शिकायत का एक अन्य क्षेत्र व्यापार और वाणिज्य है। अपनी भौगोलिक बाधाओं के कारण, नेपाल ने खुद को भारत पर बहुत अधिक निर्भर पाया है, कभी भी निर्यात बढ़ाने के लिए तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं किया है। स्थानीय उद्यम विकसित होने में विफल रहते हैं, क्योंकि वे बाजार में बाढ़ वाले कम कीमत वाले भारतीय उत्पादों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। भारत द्वारा गैर–टैरिफ बाधाओं को लागू करने और मानक बुनियादी ढांचे की कमी ने भारत के साथ नेपाल के असंतोष को और बढ़ा दिया है। निर्यात और आयात के लिए लेन–देन की लागत बहुत अधिक है। भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात गंतव्य तक पहुंचने में 42 दिन और आपूर्तिकर्ताओं के बिंदु से नेपाल पहुंचने में 35 दिन लगते हैं, जो प्रति कंटेनर यूएस + 2,700 शिपिंग लागत के लिए जिम्मेदार है। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत (कुल व्यापार का 65 प्रतिशत हिस्सा) है, जिसके साथ नेपाल सबसे बड़ा व्यापार घाटा चलाता है। 1996 में भारत के साथ व्यापार वाणिज्य संधि में संशोधन के बाद सुधार हुआ, क्योंकि निर्यात में वृद्धि हुई और घाटा कम हुआ। हालांकि, संधि के बाद के विस्तार में, भारत पहले के प्रावधानों पर वापस लौट आया, आंशिक रूप से बेईमान उद्यमियों की गतिविधियों से प्रेरित था। भारत और नेपाल के बीच एक और पुराना विवाद मौजूदा नदी संधियों के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन से संबंधित है। नेपाली हितधारकों का दावा है कि भारत ने पानी के बंटवारे में अपनी उदारता का अनुचित लाभ उठाया है, अस्पष्ट प्रावधानों का उपयोग करके और ऊपरी तटवर्ती राज्य की तुलना में बहुत कम लाभ प्रदान किया है। उनका दावा है कि कोशी और गंडकी नदियों से जुड़े मुद्दों पर भारत का रवैया संतोषजनक नहीं रहा है। महाकाली समझौता दो दशकों से अधर में लटका हुआ है। 2008 में, कोशी के तटबंध के ढहने से बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई, जिसमें भारत की एहतियाती उपाय करने में विफलता और जिम्मेदारी लेने से इनकार करने पर प्रकाश डाला गया।

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 6
November-December: 2025

1991 में, जब तत्कालीन प्रधान मंत्री गिरिजा पी कोइराला ने टनकपुर के मुद्दे पर भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो उन्हें नेपाल में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसे अस्वीकार्य रियायतों के रूप में देखा गया, विशेष रूप से बांध निर्माण के लिए भारत को 2.9 हेक्टेयर भूमि देने में। अदालत के फैसले को संसदीय अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया गया था, जो अंततः कभी नहीं हुआ। हालाँकि, टनकपुर बांध भारत के निर्माण के साथ ही एक उपलब्धि बन गया। नेपाल के नौकरशाह और जल विशेषज्ञ पिछले अनुभवों के कारण किसी भी नए ढांचे के समझौते के बारे में बात करने से हिचक रहे हैं। जैसा कि भारत–नेपाल जल सहयोग के संदर्भ में पूर्व भारतीय राजनयिक एसडी मुनि ने सुझाव दिया था, देश इनकार में प्रतीत होता है। नेपाल भारत और चीन के बीच बैठता है। हिमालय नेपाल–चीन सीमा के साथ चलता है, और नेपाल–भारत सीमा देश के दक्षिणी मैदानों में स्थित है। ट्रांस–हिमालयी रेलवे चीन और नेपाल ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बीआरआई के तहत सहयोग पर समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को तेज करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें ट्रांस–हिमालयी मल्टी–डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के ढांचे में बंदरगाह, सड़क, रेलवे, विमानन और संचार शामिल हैं। भारत ने एक वैध प्रश्न प्रस्तुत किया हैरू क्या काठमांडू तक ट्रांस–हिमालयी रेलवे आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, क्योंकि रेलवे के निचले पहाड़ों और मैदानों तक पहुंचने से पहले कई महंगी सुरंगों की आवश्यकता होती है? भारत जोखिम से अधिक खेल सकता है। सबसे पहले, काठमांडू को छोड़कर, चीनी किंघई–तिब्बत रेलवे– पहले से ही शिगात्से (जिगाज) तक पूरी तरह से परिचालित है – जल्द ही केरुंग (ग्योरोंग) में नेपाल सीमा (रासुवागडी) तक पहुंचने की उम्मीद है। केरुंग से यह काठमांडू तक 100 किलोमीटर लंबी रेलवे होगी। उस मार्ग से रेल और ट्रक की एक संयुक्त परिवहन प्रणाली यात्रा को काफी कम कर देती हैय चीन ने पहले ही शिगात्से के रास्ते लांझोउ से काठमांडू के लिए मालगाड़ी पर माल भेजना शुरू कर दिया है, जहां माल ट्रकों पर लाद दिया जाता है। पूरी यात्रा में केवल 10 दिन लगते हैं, जो कोलकाता के माध्यम से समुद्री मार्ग से होने वाले 35 दिनों से बहुत कम है। केरुंग में एक चीनी रेलवे इस प्रकार चीन–नेपाल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ा सकता है। दूसरा, केरुंग–रक्सौल (भारत) मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता अनिश्चित है, भारत परियोजना में अपनी केंद्रीयता पर जोर दे रहा है और चीन नेपाल के माध्यम से गंगा के मैदानों तक पहुंचने की योजना बना रहा है। अपने हिस्से के लिए, नेपाल चीनी रेलवे को चीनी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी और पोखरा की लोकप्रिय घाटी में लाने के अवसर के रूप में देखता है।

भारत के साथ नेपाल के संबंधों की गतिशीलता चीन के साथ अलग है। नेपाल चीन के साथ अपने जुड़ाव को एक अलग नजरिए से देखता है। बहुचर्चित कर्ज जाल के कारण, नेपाल सतर्क है

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 6
November-December: 2025

और उसने चीन से रेलवे को अनुदान के रूप में धन देने के लिए कहा है न कि ऋण के रूप में। चीन ने अपने हिस्से के लिए, अपनी अंतरराष्ट्रीय विफलताओं से भी सीखा है, चाहे वह मेजबान देशों के साथ ऋण की समस्या हो या लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता हो, जहां उसकी योजनाएं अमल में नहीं आईं। इस प्रकार, यह समझ में आता है कि चीन एक स्थिर नेपाली सरकार चाहता है, और कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों के विलय के पीछे चीन का हाथ है। रेल संपर्क और बीआरआई के बिना भी, चीन–नेपाल जुड़ाव जलविद्युत, विमानन, पर्यटन, दूरसंचार, लोगों से लोगों के बीच संबंध, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, राजनीतिक आदान–प्रदान, उद्योग और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मजबूत हुआ है। इस सब में एकमात्र अनिश्चितता चीन के अपने आर्थिक स्वास्थ्य के साथ है। केवल तीन साल पहले, दुनिया ष्चीन के महान पतनष के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि उसे स्टॉक–मार्केट क्रैश का सामना करना पड़ा था। हालांकि चीन के बारे में भविष्यवाणियां गलत साबित हुईं, कुछ परियोजनाएं वास्तव में विफल रहीं। चीन किस हद तक नेपाल में शामिल होगा यह भी आंशिक रूप से भारत और चीन के बीच उभरती बड़ी समझ पर निर्भर है।

भारत के लिए निहितार्थ – हाल के वर्षों में नेपाल में चीन की सक्रिय पहुंच आंशिक रूप से भारत की सीमा पर बढ़ती हुई ताकत से प्रेरित है, जो पहली जगह में, सीमा पर चीन की गतिविधियों के जवाब में थी। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए सीमा–बल बढ़ाने पर विचार करने का समय मोटे तौर पर नेपाल में चीन के हित में स्पाइक के साथ मेल खाता था, जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान तिब्बती विरोध के बाद और बढ़ गया। कुछ लोगों का तर्क है कि विकसित भारत– अमेरिकी संबंधों ने भी अपनी भूमिका निभाई। नेपाल में चीन की भागीदारी या तो सीधे तौर पर चीन के साथ भारत की कार्रवाई से संबंधित है, या उससे पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी भी परिदृश्य में, चीन के साथ नेपाल के जुड़ाव को न्यूनतम रखने की भारत की रणनीति अब एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। भारत–चीन युद्ध के मामले में, यह अनिश्चित है कि नेपाल 1950 की संधि (साथ ही बाद की संधियों) की भावना के अनुसार भारत का पक्ष लेगा या नहीं, अतीत में ऐसा करने के लिए नेपाल की अनिच्छा को देखते हुए। जबकि कागज पर, नेपाल भारत का सहयोगी बना हुआ है, उसने संवैधानिक रूप से कहा है कि उसकी विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, गुटनिरपेक्षता, पंचशील (और) अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रमुख दलों ने अक्सर इसे दोहराया है, और समग्र राष्ट्रीय भावना नेपाल की तटस्थ रहने की इच्छा को दर्शाती है, जैसा कि 2017 के मध्य में डोकलाम गतिरोध के दौरान हुआ था। इसके अलावा, चीन की योजना का व्यापक पैमाना और उसका आर्थिक दबदबा वैश्विक व्यवस्था के ज्वार को बदल रहा है। लैटिन अमेरिका में अमेरिका की स्थिति तेजी से नेपाल की तुलना में

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 6
November-December: 2025

भारत की वर्तमान स्थिति से मिलती जुलती है। इतना कि कभी अमेरिका का उपनिवेश माने जाने वाले पनामा ने अब बीजिंग के अनुरोध पर ताइवान के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं। अल सल्वाडोर ने ऐसा ही किया है। अब, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय वाले इंटर–अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक की 60 वीं वार्षिक बैठक चीन के चेंगदू में होने जा रही है। तत्कालीन विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की कई चेतावनियों के बावजूद बैंक के बोर्ड ने यह फैसला किया।

भारत को नेपाल के साथ नई आर्थिक, विकासात्मक और बुनियादी ढांचागत पहल शुरू करनी चाहिए जो न केवल नेपाली नागरिकों को वास्तविक लाभ पहुंचाएगी बल्कि नेपाल में उभरने वाली कमजोरियों को भी दूर करेगी क्योंकि देश चीन के साथ जुड़ता है। अब समय आ गया है कि भारत पीएम मोदी के पीएम ओली के खुश नेपाल, समृद्ध नेपाल के उद्देश्य को बार–बार समर्थन देने की कार्रवाई में तब्दील हो जाए। भारत को अपने वादों को पूरा करने की जरूरत पर नेपाल का जोर चीन की तुलना में नेपाल को अपने करीब रखने की भारत की अपनी जरूरत के बारे में जागरूकता से आता है। जैसा कि चीजें हैं, नेपाल भारत पर अपनी निर्भरता से दूर नहीं हो सकता है। भारत कई मायनों में देश के लिए महत्वपूर्ण है और रहेगा। हालाँकि, नेपाल अब चीन के विशाल BRI का सदस्य है, जो भारत को मुश्किल स्थिति में डालता है। जैसा कि ओआरएफ के विश्लेषकों, हर्ष वी. पंत और अभिज्ञान रेज ने ठीक ही कहा है, नई दिल्ली ने शी जिनपिंग के तहत एक मुखर चीनी विदेश नीति से निपटने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं पाया है। भारत को यह पता लगाना चाहिए कि वह नेपाल के मुकाबले कहां खड़ा है और बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक ढांचे, तकनीकी सफलताओं के साथ–साथ आतंकवाद जैसे नए खतरों को देखते हुए, लघु, मध्यम और दीर्घकालिक में आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। नेपाल, अपने हिस्से के लिए, एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से जी रहा है, लेकिन अपनी आबादी और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के मामले में बड़ी चुनौतियों का सामना करना जारी रखता हैय प्रेषण देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत बनाता है और ज्यादातर खाड़ी में उत्पन्न होता है। दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से मजबूत नेपाली प्रवासी हैं। इसलिए, भारत और नेपाल को यह पता लगाना चाहिए कि वे दोनों पक्षों के सर्वोत्तम हित में किन नए तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं।

निष्कर्ष– नेपाल के स्वतंत्र विदेशी संबंधों के बारे में अपनी आशंकाओं के बारे में विश्लेषक पूरी तरह सटीक नहीं हैं। एक मजबूत संप्रभु नेपाल भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक नहीं बल्कि फायदेमंद है। नेपाल चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1,400 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, शायद हिमालय का एकमात्र खंड जहां कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। एक तरह से, नेपाल ने भारत को इस अतिरिक्त 1400 किलोमीटर पर अपने बल की मुद्रा के लिए हजारों सैनिकों और सैन्य हार्डवेयर को तैनात करने की

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 6
November-December: 2025

आवश्यकता से बचने में मदद की है। भारत को 4,000 किलोमीटर लंबी चीन सीमा के साथ ऐसा करना पड़ा है, जिसने भी चीन को विवादित भूमि पर बुनियादी ढांचे के निर्माण से नहीं रोका है डोकलाम इसका एक उदाहरण है। नेपाल की संप्रभु स्थिति और स्वतंत्र नीति विकल्पों पर जोर देना और नेपाल को इन पर अमल करने में मदद करना भारत के हित में है। इसी तरह, काठमांडू के कुछ हिस्सों में संभावित त्रिपक्षीय या 21 सहयोग के बारे में चिंताएं हैं, कि भारत–चीन सौदों में नेपाल के संप्रभु हितों को कमजोर किया जा रहा है। यदि भारत अपनी सद्भावना को सार्थक कार्रवाई में बदलने का प्रबंधन करता है तो यह विश्वास बनाने में मदद करेगा। जब तक गैर–हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के सिद्धांतों का सम्मान किया जाता है और उच्च स्तर की राजनीतिक भागीदारी का पालन किया जाता है, तब तक भारत और नेपाल के नेताओं के बीच सौहार्द और सहयोग रहेगा। साथ ही वह नेपाल में अपनी सुरक्षा को लेकर चीन की बेचैनी को शांत करेगा। भारत की पारंपरिक बाहुबली कूटनीति की अवहेलना करते हुए, लगता है कि पीएम मोदी सहकारी कूटनीति की इस पंक्ति का पालन कर रहे हैं। परिणाम स्पष्ट हैं मोदी और ओली के बीच तालमेल, और मोदी की पहल में नेपाल का बढ़ता सहयोग, जो अभी एक साल पहले असंभव होता। नेपाल बिम्सटेक के माध्यम से म्यांमार और थाईलैंड के साथ सड़क से जुड़े होने की संभावनाओं के बारे में उतना ही उत्सुक है जितना कि उत्तरी मोर्चे पर बीआरआई के साथ है। इसलिए, भारत वर्तमान दृष्टिकोण को संस्थागत बनाना चाहता है, जो दोनों के सर्वोत्तम हित में प्रतीत होता है। भारत विरोधी भावना भारत के पड़ौसी देशों में सामान्य परिघटना है। अतः इन गतिविधियों से विचलित होने की बजाय, भारत की नीति नेपाल में दीर्घकालीन, जनकेन्द्रित, आर्थिक क्षमता और मानव संसाधन क्षमता के निर्माण पर आधारित होनी चाहिए। नेपाल में भारत के राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में सहयोग पर आधारित ट्रेक–2 कूटनीति का मॉडल अपनाना होगा। आर्थिक संबंध भी परस्पर लाभ के सिद्धांत पर आधारित हों ताकि नेपाल के लोगों में छोटे राष्ट्र होने की हीनभावना को कम किया जा सके। साथ ही भारत सरकार को नेपाली सरकार व वहॉ की जनता को आश्वस्त करना होगा कि उसे नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली संसद को अपने संबोधन में की और कहा की 'नेपाल सही अर्थों में सम्प्रभू राष्ट्र है और उसमें हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं है लेकिन नेपाल ने जो रास्ता चुना है (लोकतंत्र का) उसमें हम उनको सहयोग प्रदान करेंगे।' इसके साथ ही नेपाल ने भी भारत को यह आश्वासन दिया कि नेपाली भूमि का प्रयोग किसी भी तरह से भारतीय हितों के खिलाफ नहीं किया जाएगा।

GYANBODH
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN:3048-9792
Volume: 2
Issue: 6
November-December: 2025

संदर्भ

1. विनय, ''पड़ौस में सरकार का इन्जार'' राजस्थान पत्रिका, जनवरी, 18, 2011, पृष्ठ 8.
2. कुमारी, डॉ प्रवेष, 'उभरते लोकतत्र में संविधान निर्माण की समस्याः नेपाल के संदर्भ में वर्ल्ड फोकस , नवम्बर 2012 पृष्ठ संख्या–50
3. The Hindu, January 29, 2011.
4. Murthy Padmaja, "Challenges to India's foreign policy in Nepal", worldfocus, Nov.-Dec., 2010, PP. 605-611.
5. www. opendemocracy.net/leena/rikkalatamagnepal.com, Hindustan 4 June, 2012
6. Khannal Elected PM- The Times of India, Feb. 4, 2011.
7. Hindustan, 29 August, 2011.
8. Netindian news networks, India, "Nepal agree to cooprate to fight Terrorism", New Delhi,January 17, 2010
9. see website http.//netindian.in/news/2010/01/17/000489/india-nepal-agree-cooperate-fight-terrorism.
10. सिंह रहीस 'अंतर्राष्ट्रीय संबंध' Lexisnexis Haryana India, 2016
11. Jaiswal pramod, "India-China power game in Nepal & the consequences", Indisute for Defence Study and Analysis (IDSA), New Delhi, Sept. 16, 2010.
12. Murthy Padmaja, "Challenges to India's foreign policy in Nepal", worldfocus, Nov.-Dec., 2010, PP. 605-611.
13. Gupta Arvind, "India needs a new paradigm in its Nepal policy", Insitute for Defence Study and Analysis, (IDSA), New Delhi, Aug. 18, 2010.
14. Nayak Nihar, "Maoists shetoric on India-Nepal relations", Institute for Defence Study and Analysis, (IDSA), New Delhi, January 13, 2010.
15. Gupta Arvind, "India needs a new paradigm in its Nepal Policy", Institute for Defence Study and Analyses, (IDSA), New Delhi, August 18, 2010.
16. विस्वास तपन (2016) 'अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरियंट ब्लॉक स्वान प्राइवेट लिमिटेड वर्ल्ड फोकस नवम्बर 2016
17. Prashant Jha ―How India was both Right and Wrong to Nepal‖ *Hindustan Times* 20 Jan 2015